गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सड़कों का निर्माण

5998. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों से सम्बन्धित योजनाओं की गति बढ़ाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) से (ग) सड़कों का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य का विषय है तथा इसके लिये निधियां राज्य योजना/बजट में उपलब्ध कराई जाती हैं। यह मंत्रालय गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सड़कों के निर्माण की कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है अथवा किसी योजना के लिये निधियां उपलब्ध नहीं करा रहा है।

Seizure and auction of Bapu Kuta

5999. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that "Bapu Kuti" the mud-wallked, tiled-house at Seva Gram where Mahatma Gandhi guided country's destiny for several years, has been seized and auctioned by Revenue Authorities for non-payment of agricultural land tax;

(b) if so, whether State Government have requested for exemption of agricultural land tax;

(c) if so, whether the Centre has already issued any directions to the State Government not to seize and auction the same; and

(d) if so, the reaction of the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT): (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) No, Sir. The 'Bapu Kuti' mud-walled, titled house at Seva Gram has neither been seized nor auctioned and also no agricultural land tax has been levied thereon.

(b) to (d) In view of (a) above, question does not arise.

Offer from Netherland Government on Salinity Prevention

6000. SHRI AHMED MOHMEDBHAI PATEL: Wiill the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Netherland Government have offered aid to prevent the spread of salinity in the Kutch and Bhavnagar districts of Saurashtra;

(b) if so, what is the total amount of aid which that Government has agreed to provide for completion of this project;

(c) whether the Madhya Pradesh Government has prepared a Project Plan to prevent Salinity in the Malia-Lakhpat area of Kutch @Rs. 15 crores:

(d) whether the State Government had appointed a Committee in 1976 to carry out a detailed survey of the coastal strip from Madhavpur, Una, Bhavnagar to Lakhpat for prevention of salinity;

(e) whether all the recommendations are being implemented with the help of World Bank also; and

(f) if so, what are the total areas to be covered under the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) The project is under consideration of the Netherland Government and the final quantum of aid will be decided after finalisation of the project agreement.

(c) No such project has been forwarded to this Department by the State Government of Gujarat;

(d) to (f) As no funds of the Central Government are involved the information in regard to these points is not monitored at level of the Central Government.

ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप योजना का कार्यान्वयन

6001. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रो मे नलकूप योजना लागू करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह योजना, 1981 की जनगणना के अनुसार एक निश्चित आबादी वाले गांव में ही लागू की जानी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 1981 के निर्धारण वर्ष को बदलने पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले मे अंतिम निर्णय क्या लिया गया था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल) : (क) हैंडपंप योजनाओं के मामले में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन 1986 की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्रत्येक 250–300 व्यक्तियों के लिये एक पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जाना है। आवासीय कनेक्शनों के वगैर सार्वजनिक स्टैंड पोस्टों की मार्फत पेयजल हेतु पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनायें तैयार की जाती हैं। योजनायें 10–15 वर्ष की अवधि के लिये प्रक्षिप्त जनसंख्या 1981 के जनगणना आबादी के 40% मे अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) योजनाये गांवो मे विशेष जनसंख्या वर्ग की शर्त के बिना सभी गांवों/बसावटों पर लागू होती हैं। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मशती कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये योजनाओं हेतु 100 लोगों के लिये एक जल स्रोत वाला मानदंड अपनाया गया था। स्वतंत्र बस्तियों/बसावटों के मामले में एक पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जाता है यदि निर्धारित 1.6 कि० मीटर की दूरी मानदण्डो के भीतर स्वच्छ पेयजल का कोई जल स्रोत उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) 1981 की जनगणना के आधार वर्ष की जनगणना आंकड़े प्राप्त हो जाने के पश्चात परिवर्तन करके 1991 जनगणना वर्ष कर दिया गया है।

हाई प्रेशर बोर वैल आदि के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव

6002. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हाई प्रेशर डीप बोर वैल, कम्बीनेशन ड्रिलिंग रिग तथा हाइड्रोप्रेक्चरिंग यूनिट की क्रय किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या उसे स्वीकृति दे दी गई है ; और